

हताशा को हर हाल में हराने का हौसला



हरिवंश चतुर्वेदी | महानिदेशक, आईआईएलएम

ते दिनों आईआईटी, रुड़की की बोटक दूसरे वर्ष की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। इस संस्थान में पिछले एक साल में आत्महत्या का यह तीसरा मामला था। आईआईटी संस्थानों में देश के प्रखर छात्र-छात्राओं को ही दाखिला मिलता है। ऐसे में, वहां हर साल आत्महत्या के कई मामलों का सामना आना चिंता की बात है। वास्तव में, आईआईटी ही नहीं, देश के हरेक कोने में विद्यार्थियों में खुदकुशी की बढ़ती प्रवृत्ति चिंताजनक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो दशकों में विद्यार्थियों में जान देने के मामले चार प्रतिशत की दर से बढ़े हैं, जबकि कुल आत्महत्या में दो फीसदी की दर से वृद्धि हुई है। पिछले एक दशक (2014-24) में तो यह पाया गया है कि छात्रों में आत्महत्या की दर नौजवानों की जनसंख्या वृद्धि दर से ज्यादा रही है। 2014-15 में विद्यार्थियों की आत्महत्या के 6,654 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2023-24 में बढ़कर 13,044 हो गए।

एनसीआरबी के आंकड़ों पर आधारित आईसी3 इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट (2024) के अनुसार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं, जो विद्यार्थियों की खुदकुशी के मामले में सबसे ऊपर हैं। यह सही है कि देश के तमाम शहरों में छात्र आत्महत्या करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शहर भी हैं, जहां यह समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। इनमें राजस्थान का कोटा शहर सबसे ज्यादा बदनाम है। साल 2023 में यहां 26 किशोरवय छात्रों ने आत्महत्या की थी। साल 2024 में इस संख्या में जरूर गिरावट आई और 17 ऐसे मामले दर्ज किए गए, लेकिन बीते एक महीने में यहां छह छात्र अपना जीवन खत्म कर चुके हैं।

कोटा छात्रों की आत्महत्या का गड़ क्यो बन गया है और राज्य सरकार इसे क्यों नहीं रोक पा रही, इस पर कई बार अध्ययन हो चुके हैं। दरअसल, पिछली सदी के 60 के दशक में कोटा उत्तर भारत का एक प्रमुख औद्योगिक शहर बन गया था, जहां कई औद्योगिक

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो दशकों में विद्यार्थियों में जान देने के मामले चार प्रतिशत की दर से बढ़े हैं। क्या हम इस पर लगाम लगा सकते हैं?



घरानों ने बड़ी-बड़ी फैक्टरियां स्थापित की थीं। सन् 1991 के उदारीकरण से पहले अधिकांश उद्योग-धंधे बंद हो गए और वहां एक नए उद्योग का जन्म हुआ, जिसे 'कोचिंग इंडस्ट्री' कहते हैं।

कोटा देश का वह शहर है, जहां जेईई और नीट की तैयारी करने वाली कई बड़ी-बड़ी कंपनियां संचालित होती हैं। यह कोचिंग का फैक्टरी मॉडल है। इन कोचिंग कंपनियों के पास बड़े-बड़े ऑडिटरियम हैं, जहां छात्र-छात्राओं को कुछ नामचीन अध्यापक पढ़ाते हैं। अपनी संतान को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए देश भर के मध्यवर्गीय अभिभावक 14 से 18 साल के बच्चों को इन कोचिंग संस्थानों में लाखों रुपये की फीस देकर दाखिला दिलाते हैं। ये कोचिंग संस्थान इन किशोरों को दिन में 12 से 16 घंटे पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं, जिसका दबाव बहुत से छात्र नहीं झेल पाते। इनमें से अधिकांश निजी छात्रावासों में रहते हैं और मानसिक रोगों के शिकार बन जाते हैं। यहां के कोचिंग उद्योग के सफेद व स्याह पहलुओं को नेटफ्लिक्स की एक सीरीज

ने बहुत अच्छे ढंग से उजागर किया था।

14 से 22 वर्ष की आयु वाली पीढ़ी हमारे देश का भविष्य है। भारत का 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना कुछ हद तक इस बात पर भी निर्भर करेगा कि हम देश के इन 25 करोड़ नौजवानों को मानसिक रोगों, खासतौर से 'डिप्रेशन' से किस हद तक बचा पाते हैं? यह हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि मानसिक रोगियों को हिकारत की नजर से देखा जाता है। बच्चों को निराशा और हताशा से बचाने की जिम्मेदारी सरकारों के साथ-साथ उन अभिभावकों की भी है, जो अपने अधूरे सपनों को बच्चों के ऊपर लादकर तमाम तरह की हसरतें पाल बैठते हैं। सवाल है कि शिक्षित युवा और विद्यार्थी अपने जीवन का खुद गला क्यों घोटते हैं? क्या वे खुदकुशी से पहले अपनी बेचैनी के संकेत अपने परिजनों, संगी-साथियों या शिक्षकों को नहीं देते? अगर ऐसे संकेत मिलते हैं, तो उन्हें समय पर मनोचिकित्सा देकर क्यों नहीं बचा लिया जाता?

हर साल जब जेईई और नीट के रिजल्ट घोषित

किए जाते हैं या दसवीं-बारहवीं के परिणाम आते हैं, तो मोडिया में असफल विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या की खबरें भी आने लगती हैं। तमिलनाडु जैसे कई राज्यों में यह एक गंभीर समस्या बन चुकी है। परीक्षा में फेल होने बाद की जाने वाली आत्महत्या हमारी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में निहित भयंकर बीमारी का संकेत देती है। एक तरफ आर्थिक विकास के बावजूद रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ, हमारा समाज हर कामयाब इंसान को धीरे की तरह पूजता है। क्या जिंदगी में हर इंसान हरेक बार सफल हो सकता है? क्या जिंदगी में सफलता-विफलता साथ-साथ नहीं चलती?

छात्र-छात्राओं की खुदकुशी से यह सवाल भी उठता है कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई संगठित और व्यापक प्रयास नहीं किए जा सकते? क्या हमारी शिक्षा-व्यवस्था छात्रों को आत्महंता बनने से नहीं रोक सकती? क्या ऑक्टोपस की तरह छात्रों के भविष्य को जकड़ती कोचिंग इंडस्ट्री पर प्रभावी निबंधन नहीं लगाए जा सकते? क्या जेईई और नीट जैसी राष्ट्रीय परीक्षाएं सिर्फ शीर्षस्थ पांच प्रतिशत प्रतिभाओं के लिए बनाई गई हैं और शेष 95 फीसदी छात्रों को कोई अन्य अच्छे अवसर नहीं दिए जा सकते?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 ने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली को उनके समग्र विकास का मूल आधार मानते हुए कई रचनात्मक सुझाव दिए थे। इनमें हर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में काउंसलर व मनोचिकित्सक नियुक्त करने, पढ़ाई के बोझ व उससे पैदा होने वाले तनाव को कम करने, रटने-रटाने की प्रवृत्ति को रोकने, जिंदगी जीने की कला सिखाने, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने, कैंपस को समावेशी व सुरक्षित बनाने और परिवार व शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के सुझाव दिए गए थे। इन पर कितना अमल हो पाया है, इस पर रवेत-पत्र जारी होना चाहिए।

हकीकत यह है कि देश में हर पांच में से दो इंसान मानसिक रोगों से पीड़ित है और एक लाख की आबादी पर हमें कम से कम तीन मनोचिकित्सक की जरूरत है, लेकिन यह संख्या बमुश्किल एक भी नहीं पहुंच रही। क्या स्वास्थ्य मंत्रालय मनोचिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों और काउंसलरों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई योजना नहीं बना सकती? शिक्षित युवाओं में फेल खी हताशा को रोकने में ऐसे उपाय कारगर हो सकते हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

Times of India

Human Trafficking escalates by anonymity & complex network in digital age, says NHRC Chairman

<https://timesofindia.indiatimes.com/city/raipur/human-trafficking-escalates-by-anonymity-complex-network-in-digital-age-says-nhrc-chairman/articleshow/118093703.cms>

TNN | Feb 9, 2025, 09.32 PM IST

RAIPUR: National Human Rights Commission and Hidayatullah National Law University jointly organized a conference on 'Combating Human Trafficking in the Digital Age', at the law university premises on Feb 7. NHRC chairperson urged for the need of effective national and international steps to combat the crime of human trafficking. Delivering the Inaugural address, the chairperson of NHRC, Justice Ramasubramanian underlined the huge surge in human trafficking from the data available which require awareness in digital navigation and International collaboration to contain this organized crime which is carried out with the aid of the complex digital network. He urged the younger generation for appropriate safe practices when using the net with social media in particular.

R Shangeetha, secretary and commissioner, excise, commercial tax department in Chhattisgarh, delivering the address as guest of honour narrated her field experience of tackling the menace of human trafficking and the measures taken by the CG government to combat it. She lamented that most of the cases do not result in conviction for lack of procedural rigour and urged the law student to take a proactive role in building awareness, helping the victims and joining hands with the efforts of the Government,

Earlier in giving the opening remarks, Prof. Dr. Vivekanandan, Vice Chancellor of HNLU traced the history of human trafficking during colonial times as indentured labour, slavery from the African continent and continuing in modern times cashing on issues of poverty, internal conflicts, war and gullibility of juveniles. He remarked that the digital aid of such crime has not got the due attention and require an effective legal framework taking digital complexities into account.

The conference's first panel discussion had the theme of "Role of the Internet in Facilitating Human Trafficking and Migrant Smuggling – A Legal and Regulatory Perspective," dealing with internet facilitation of human trafficking and migrant smuggling, which complicates the enforcement efforts. The key recommendations that the officials gave were strengthening cybercrime and anti-human trafficking units with trained personnel, expanding AI and cyber surveillance to track traffickers and identify victims, mandating ISP cooperation for monitoring and reporting trafficking-related activities, enhancing victim rehabilitation programs to prevent re-trafficking.

The second panel discussion session titled “Preventive Strategies Against Human Trafficking: Role of Technology, Law Enforcement Agencies, Victim Support, and Community Engagement,” focused on preventive strategies to combat human trafficking, emphasizing technological interventions, law enforcement coordination, victim rehabilitation, and community engagement.

The key recommendations by dignitaries included leveraging technology like AI, geo-tagging, and cyber tools to track trafficking activities and aid law enforcement, strengthening victim support with safe houses, psychological care, and financial assistance programmes, raising awareness in vulnerable communities to prevent recruitment by traffickers.

Times of India

NHRC asks chief secy to frame SOP for reducing lightning deaths

<https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/nhrc-asks-chief-secy-to-frame-sop-for-reducing-lightning-deaths/articleshow/118092909.cms>

Feb 9, 2025, 08.35 PM IST

Bhubaneswar: National Human Rights Commission (NHRC) has asked the Odisha chief secretary to frame a standard operating procedure (SOP) and guidelines to reduce deaths due to lightning. The state reported 1,625 lightning deaths in the past five years.

The commission passed the order on Thursday after hearing a petition filed by human rights activist and lawyer Radhakanta Tripathy, an Odisha native. The petitioner stated that incidents of deaths due to lightning and thunderbolt were reported from different districts, but the govt had not made any proper action plan to minimise the casualties.

NHRC took cognisance of the matter and heard both parties. Tripathy suggested several steps in detail to reduce the fatalities and injuries from lightning. He also stressed formulating an SOP for providing compensation and support to the victims' families.

NHRC received suggestions of the complainant to reduce fatalities due to lightning. These suggestions included public awareness and education, real-time weather forecasting and warning systems by installing advanced lightning detection systems across the state, safe shelter initiatives, infrastructure and building regulations, training for emergency responders, data collection and research, promoting lightning safety practices, improved disaster management plans, and community resilience building.

The commission also received the complainant's suggestions for the govt to bring out a clear and effective SOP for providing compensation and support to the victims' families. It includes identification and verification of lightning deaths, communication and coordination, compensation eligibility criteria, compensation account, documentation required, processing the compensation claim, timely disbursement, record keeping and monitoring, creating public awareness and outreach, and holding training and capacity-building exercises.

"Since the Odisha govt has already been working to reduce the fatalities, the commission is of the view that suggestions submitted by the complainant may be considered by the state govt for further policy framing in this regard. In view thereof, let a copy of the complainant's communication be sent to the Odisha chief secretary for necessary action at their end. With this direction, the case is closed," the NHRC order said.

The Statesman

NHRC seeks SOP for providing relief to lightning victims' families in Odisha

National Human Rights Commission (NHRC) has directed the Odisha Government to formulate a standard operating procedure (SOP) to provide monetary succor to the lightning victims in the State.

<https://www.thestatesman.com/india/nhrc-seeks-sop-for-providing-relief-to-lightning-victims-families-in-odisha-1503396155.html>

Statesman News Service | BHUBANESWAR | February 9, 2025 5:57 pm

National Human Rights Commission (NHRC) has directed the Odisha Government to formulate a standard operating procedure (SOP) to provide monetary succor to the lightning victims in the State.

Acting on a petition filed by human rights lawyer Radhakanta Tripathy, the NHRC passed the order asking the State's Chief Secretary to do the needful in this regard. The petition had sought for the expeditious relief to the victims' families.

“Tripathy has suggested several steps in detail to reduce the fatalities and injuries from lightning which are discussed in preceding paragraphs in brief. The complainant also stressed to formulate a SOP for providing compensation and support to the victims' families. Since, the Government of Odisha, has already been working to reduce the fatalities, the Commission is of the view that suggestions submitted by the complainant, may be considered by the Government of Odisha, for further policy farming in this regard”, NHRC asked in an order.

Earlier the State Government had submitted that a SATARK APP has been developed to provide early warning on lightning and thunderstorms.

Lightning has been recognised as Natural Calamity u/s 3(1) of the Odisha Relief Code and has been categorised as “State Specific Disaster” by the Odisha State Disaster Management Authority (OSDMA).

The petition had suggested among other things steps in detail to reduce the fatalities and injuries from lightning on steps like public awareness, real-time weather forecasting and warning systems by installation of advanced lightning detection systems across the state and safe shelter initiatives. Other steps include Infrastructure and building regulations, training for emergency responders, data collection and research, promoting lightning safety practices, improved disaster management plans and community resilience building.

The petitioner further suggested that to manage and address lightning-relating deaths, it is important to have clear and effective SoP for providing compensation and support to the victims' families having outline of the points including identification and verification of lightning death, communicating and coordination, compensation eligibility criteria, compensation account and expeditious processing the compensation claim.